PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Though he has read it in English, he has written it in Devanagari script as a compromise !

(vii) Production and Screening of films relating to Independence Movement by Films Division

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित आगामी नवम्बर, 1984 तक फिल्म डिवीजन के द्वारा कुछ विशेष फिल्में तैयार की जा रही हैं। उन फिल्मों को मई और नवम्बर, 1984 के बीच सारे देश में प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं सरकारी माध्यमों द्वारा इस संबंध में विशेष कार्यक्रम प्रकाशित किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि फिल्म डिवीजन में काफी पहले से ही स्वतन्त्रता आंदोलन से संबंधित दर्जनों फिल्में तैयार पड़ी है। इसलिए उन्ही विषयों पर करोड़ों रुपए खर्चा कर नई फिल्में बनाने का क्या औचित्य है। आम लोगों के दिमाग में यह सन्देह है कि इन फिल्मों एवं कार्यक्रमों का उपयोग आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल द्वारा किया जायेगा। स्वतन्त्रता आन्दोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था वे प्रायः सभी दलों से हैं। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास को तोड़े-मरोड़े जाने की सम्भावना है।

अतः सरकार से मांग है कि फिल्म रिलीज़ करने से पहले प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों एवं सभी दलों के नेताओं से राय ले ली जाए।

(viii) Financial assistance to farmers of Rajasthan whose crops were destroyed due to cold wave

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकस्मात् कारणों से और सर्दी की लहर जो कि राजस्थान में लम्बे अर्से तक रही, चने और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। गरीब किसानों ने बहुत बड़ी उम्मीदें की थीं लेकिन वे सभी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। चने की फसल, खासकर राजस्थान के कुछ जिलों में तो बिल्कुल खत्म हो गई। बहुत दिनों के बाद राजस्थान में सरसों की फसल बढ़िया हुई थी, लेकिन इस शीत लहर ने भारी नुकसान पहुंचाया।

मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वह उन गरीब किसानों को जिनका सहारा ये ही फसलें थीं, उनकी मदद के लिए कुछ उपाय सोचे। जैसे और प्रान्तों में केन्द्र सरकार ने ऐसे मौके पर केन्द्रीय सहायता दी है, उसी हिसाब से राजस्थान के किसानों को भी केन्द्रीय सहायता दी जाय।

(ix) Demand for more railway services for Bijnor

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बिजनौर के मुख्यालय से लखनऊ, हावड़ा तथा इलाहाबाद से सीधी रेल सेवा की व्यवस्था के अभाव में वहां के निवासियों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराने की ओर ले जाना चाहता हूं। कोई भी सीधी रेलगाड़ी लखनऊ, इलाहाबाद तथा हावड़ा तक बिजनौर होकर नहीं जाती है। क्षेत्रीय जनता की बराबर यह मांग रही है कि नजीबाबाद से होती हुई देहरादून से जो जनता एक्सप्रेस चलती है, उसको बिजनौर से गजरौला होते हुए मुरादाबाद को निकाल दिया जाए और वह फिर लखनऊ जाए या एक दूसरी रेलगाड़ी (एक्सप्रेस या पैसेन्जर) बिजनौर से लखनऊ तक चलाई जाए जो लखनऊ से दिल्ली के मध्य की सवारियों को सुविधाजनक हो। नहीं तो कम से कम दो डिब्बे बिजनौर से नजीबाबाद तक और दो डिब्बे बिजनौर से गजरौला तक लखनऊ मेल में लगवाये जायें और देहरादून से हावड़ा जाने वाली 10 डाउन में जोड़े जायें—जो एक प्रथम श्रेणी एवं एक द्वितीय श्रेणी का हो।

नजीबाबाद, बिजनौर और नगीना रेलवे स्टेशनों के पास रेलवे फाटकों के पास सड़कों के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने की भी अत्यधिक यातायात से होने वाली दुर्घटनाओं एवं चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने की दिशा में अत्यावश्यक है।

[श्री मंगलराम प्रेमी]

जनता एक्सप्रेस जो देहरादून से बनारस जाती है उसे मौजापुर नारायण पर रोका जाए क्योंकि मौजापुर नारायण एक जंक्शन है, सभी जगह को रेलें वहां से होकर निकलती हैं।

अत: माननीय रेल मन्त्री जी से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दिलचस्पी लेकर अविलम्ब कारगर एवं प्रभावी कदम उठाने का कष्ट करें, ताकि लोगों में रेल सुविधाओं का लाभ पहुंचे और रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी।

(x) Need to declare Amravati as industrially backward district

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आदिवासी जनता का बाहुल्य है। यह जिला अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ रहा है। सर्वत्र गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है। शिक्षा की दृष्टि से समुन्नत होते हुए भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इस क्षेत्र में काफी अधिक है। युवकों में गहरी निराशा फैली हुई है। खनिज पदार्थ वन सम्पदा और कृषि की दृष्टि से समृद्ध होने पर भी अमरावती में इनके व्यावसायिक उपयोग की कोई योजनायें न होने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं है। अमरावती परस्पर विरोधाभास का मूर्त रूप है। हथकरघा बुनकरों की कला और शिल्प के लिए विख्यात इस जिले में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने की कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं है। बड़ा उद्योग का तो नाम मात्र भी नहीं है। पिछली बार जब मैंने इसी आशय का एक प्रश्न लोकसभा में उठाया था तो सरकार ने यह उत्तर दिया कि इस विषय पर विचार किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि शिवरामन समिति को यह मामला निर्दिष्ट कर अमरावती को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए और इसे अधिसूचित कर आदिवासी प्रधान अमरावती क्षेत्र के प्रति अन्याय का निवारण किया जाए।

(xi) Need to provide residential accommodation to traders of Kashmir in Delhi

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Numerous housing colonies came up in Delhi for various categories of people during the past three decades. The fruit growers and merchants from the J and K State who make a livelihood from this industry have to be in Delhi for most part of the year as the sole marketing place for Kashmir fruit happens to be in Azadpur in Delhi. These merchants/growers have been facing great hardship in the absence of proper residential accommodation. They have been pressing their demand for a pretty long time. The most convenient thing would be to accommodate Kashmiri fruit growers in the Shalimar housing complex, which is in the vicinity of Azadpur market. Alternatively, land could be allotted to them at some convenient place. This matter can hardly brook any further delay.

Another category of people are the labourers who are mainly dependent on this industry and have per force to migrate to Delhi for over six months every year. It would be in the fitness of things to build a Sarai in the Azadpur Market complex to accommodate such people during their stay in Delhi. India being a welfare State, it should take measures whereby weaker sections can derive benefit through the Central Government's welfare measures.

---

14 22 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported failure of Delhi Development Authority to allot land to a large number of Group Housing Societies

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : I call the attention of the Minister of Works and Housing to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

"The reported failure of the Delhi